



















शनिवार, 6 सितंबर 2025



यह नियम बना लीजिए कि आप कभी भी अपने बच्चे को ऐसी किताब न दें, जिसे आप खुद न पढ़ें।

-जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता

### पर्यावरणीय अनुशासन जल्दी

उच्चमंत्र न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा पंजाब में बार-बार हो रहे अभूतपूर्व भूखलों एवं प्रलयकारी बाढ़ के संदर्भ में पहाड़ों पर हो रही पेंडों की अंधाधूंध अवैध कटाई को जिम्मेदार ठहराया है। उसने इसके लिए एसएआई जांच कराने का आदेश दिया और केंद्र सरकार तथा राष्ट्रीय आपादा प्रबंधन प्राथिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राथिकरण जैसी एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी कि हमारी संविधान एजेंसियों को पारिस्थितिक और हिमालयी क्षेत्र में जमीन तथा नदियों को क्षण से बचाने में विफल रही है। यह चेतावनी समयावधि भी है और आवश्यक भी, क्योंकि इस कठोर संचय से हम अब नहीं मंडू सकते कि हमारा विकास नहीं नियतर किया है। अब अति ही जाने के बाद वह जबवाब देने लगी है, हालांकि केवल वर्षों की कटाई ही इसके कारण नहीं है। मैदानी इलाकों में नदी के पाटों या उसके मार्ग का अतिक्रमण, जल निकासी तंत्र का लोप, अवैज्ञानिक बांध निर्माण, अतिक्रमणकारी शहीदीकरण और औद्योगिक प्रदूषण भी बाढ़ की गंभीरता को कई गुना बढ़ाते हैं। इसी तरह पहाड़ों में अनियंत्रित सङ्कट निर्माण, बिना भूगर्भीय अध्ययन के सुरंग और बांध परियोजनाएं, अनियंत्रित पर्यटन ढांचा और निर्माण सामग्री के लिए अनवरत खनन भूखलों को आवैधत करते हैं। पर सतत विकास भी एक अनिवार्य तरह है, उसकी अनंतरी कैसे की जा सकती है? पर्यटन, सङ्कट और विजली जैसी आधारभूत सुविधाएं पहाड़ी राज्यों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। सवाल यह है कि संतुलन के सबैने!

इसके अनुत्तरात् अनुत्तरात् अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रबंधन में निहित है। सबसे पहले, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना बनानी होगी, जिसमें स्थानीय औपालिक स्थिति के अनुसार निर्माण मानक तय किया जाएं और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण के बिना किसी बड़ी परियोजना को अनुमति न दी जाए। पर्यटन को 'कैरीड़न कैपेसिटी' के सिद्धांत पर आधारित किया जाए, यानी जितनी संख्या तक पर्यावरण वहन कर सकत है, उतनी ही अनुमति हो। दूसरा, वर्षों की पुनर्स्थानी और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को गंभीरता से लागू किया जाए और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमणों को हटाकर शहीरी जल निकासी तंत्र को दुरुस्त किया जाए। तीसरा, आपदा प्रबंधन एजेंसियों की जबवाबदी और क्षमता दोनों को मजबूत करना होगा। केवल चेतावनी देने वाली व्यवस्था एवं पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी के स्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्वास तंत्र को भी सशक्त समुदायों की भागीदारी से त्वरित प्रतिक्रिया और अपनवास तंत्र को भी सशक्त करना चाहिए, निःसंदेश इसके लिए जन जागरूकता अत्यावश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकारें और एजेंसियों विकास को पर्यावरणीय अनुशासन और संतुलन के अनुष्ठान रखें। स्थानीय विकास प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि हम या तो समय रहते इस संतुलन को साधते, या फिर बार-बार आपदाओं की कीमत चुकाते रहें। यह वक्त है जब नीति और नियमन की सख्ती को विकास की गति के साथ जोड़ा जाए, तभी पहाड़ों की मजबूती और मैदानों की सुरक्षा व समृद्धि दोनों सुनिश्चित हो पाएंगे।

### प्रसंगवाच

### गिरदों की कमी से हर साल एक लाख लोगों की मौत

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों, जैसे कि कुरुओं और चीलों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब गिरदों कम हो जाते हैं, तो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरद, मृत जानवरों का अवशेष सहजता से नष्ट कर परिस्थितिको का स्वच्छ बनाए रखते हैं। पिछले कुछ दशकों में, गिरदों की कई प्रजातियों जैसे कि व्हाइट-बैक गिरद, लॉन्ग-बिल्ड गिरद और स्ट्रेंडर-विल्ड गिरद विलूत होने वाली कीरण पर आ गई हैं।

इनके अनुपस्थित रहने से नियंत्रक जैव-विविधता खतरे में पड़ती है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और सामाजिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनकी संख्या में गिरावट से यह संकट अब एक आपादा जाली है।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

1980 के दशक में भारत में गिरदों की संख्या करोड़ों में थी, लेकिन 1990 के दशक के अंत तक यह संख्या तेजी से नियंत्रित हो गई। गिरदों की गिरावट की संख्या के पीछे गिरदों की गिरावट की संख्या तेजी से नियंत्रित हो गई।

भारत में गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

गिरदों की कमी तंत्र का हिस्सा होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

### बदलती विधव की राजनीति और वाड का भविष्य



दिव्यदेव सिंह

कानपुर



हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने, समुद्री सुरक्षा, आंतरिकवाद के निराध, साइबर सुरक्षा और आर्थिक व बनायी दाँचों बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने के उद्देश्य से अमेरिकी नेतृत्व वाली सरकार ने अपने बच्चों के बढ़ते प्रभाव का अस्तित्व संकेत में पड़ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेनो इशिगो द्वारा चीन के प्रति नरम है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारत की तरह जापान से भी चीन रिश्ते मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

अगर ऐसा होता है तो वाड का अस्तित्व बनाया रहेगा, कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाड का गठन ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा की वाड का अस्तित्व संकेत में उन्हें 'टैक टैक' कहा जाता है। यह भी माना था कि राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें ज्यादा बहर वाताने के बाद वार्ता करने के लिए एक अवधारणा है। वाड का अस्तित्व संकेत में उन्हें ज्यादा बहर वाताने के बाद वार्ता करने के लिए एक अवधारणा है।

अगर ऐसा होता है तो वाड का अस्तित्व बनाया रहेगा, कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाड के दौरान एक विकल्प के बाद वार्ता करने के लिए एक अवधारणा है। अगर ऐसा होता है तो वाड का अस्तित्व संकेत में उन्हें 'टैक टैक' कहा जाता है। यह भी माना था कि राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें ज्यादा बहर वाताने के बाद वार्ता करने के लिए एक अवधारणा है।

इस सम्मेलन पर अमेरिका लगातार वारीकर नज़र रखे थे। अब सम्मेलन की अंतिम तरह जापान के लिए एक अवधारणा की वारीकर नज़र रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाड का अस्तित्व संकेत में उन्हें 'टैक टैक' कहा जाता है। यह भी माना था कि राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें ज्यादा बहर वाताने के बाद वार्ता करने के लिए एक अवधारणा है।

इस सम्मेलन पर अमेरिका लगातार वारीकर नज़



बाजार	सेसेक्स ↓	निफ्टी ↓
बंद हुआ	80,710	24,741
गिरावट	7.25	6.70
प्रतिशत में	0.01	0.03

सोना - 1,06970  
प्रति 10 ग्राम  
चांदी - 1,25,600  
प्रति किलो

# अमृत विचार

योग्याधा, शनिवार, 6 सितंबर 2025

www.amritvichar.com

# कारोबार

## जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को

सीबीआईसी ने कहा- अभी की कीमत और जीएसटी में सुधारों के बाद की कीमतों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली, एजेंसी

जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाया, इसके लेकर कथासों का दौर जारी है। इसे बीच केंव्रिय अप्रवास कर और सीमा शुल्क बोई ने स्पष्ट किया है कि कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंचे इसके लिए उत्थानता मामलों के मंत्रालय एवं अन्न संबंधित विभागों के साथ मिलकर कीमतों समेत समूची स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सकार जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिलाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए सीबीआईसी, उपचारक मामलों के मंत्रालयों समेत सभी संबंधित पर नजर रख रहा है। अग्रवाल ने एक बातचीत में कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों के तहत एक तरह के समान को एक ही कर दायरे में लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से विवादों में कभी आने की उम्मीद है।

सीबीआईसी चेयरमैन ने कहा कि अगर दर कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं मिलने की विकासताती है, हम उसे उद्योग संगठनों के पास ले जायें। उद्योग संगठनों ने कहा है कि दरों में कटौती से जो भी लाभ होगा, उसका फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि सकार ने कदम उठाया है, प्रक्रिया को सरल किया गया है। उद्योगों को एक निश्चितता दी गयी है। ऐसे में उनका भी दायित्व बनता है। हमें प्राप्त विश्वास है कि वे जो भी लाभ हैं, ग्राहकों को दें।

एक सबल के जवाब में उन्होंने कहा, "जो माल पहले से बाजार में है और उस पर एमआरपी पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होती है, तो उसकी दर 20 करोड़ रुपये का शुल्क लाभ दर्ज किया गया है। और योंने एक विशेष दर 10 करोड़ रुपये का शुल्क लाभ दर्ज किया गया है। उनमें 10 से 15 दिनों के रुख पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हम देख



### अब विवाद की संभावना नहीं: अग्रवाल

अग्रवाल ने कहा कि कंपनियों के लिए जीएसटी वार्ता में सल और पारदर्शी हो गया है और विवाद की सभावना लाभग्रहण छह हो गयी है। रिफंड, पॉकिंगण प्रक्रियाओं को तेज उठाकोई दिवकरन नहीं है।

नई दिल्ली, एजेंसी

जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाया, इसके लेकर कथासों का दौर जारी है। इसे बीच केंव्रिय अप्रवास कर और सीमा शुल्क बोई ने स्पष्ट किया है कि कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंचे इसके लिए उत्थानता मामलों के मंत्रालय एवं अन्न संबंधित विभागों के साथ मिलकर कीमतों समेत समूची स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सकार जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिलाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए सीबीआईसी, उपचारक मामलों के मंत्रालयों समेत सभी संबंधित पर नजर रख रहा है। अग्रवाल ने एक बातचीत में कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों के तहत एक तरह के समान को एक ही कर दायरे में लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से विवादों में कभी आने की उम्मीद है।

सीबीआईसी चेयरमैन कहा कि अगर दर कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं मिलने की विकासताती है, हम उसे उद्योग संगठनों के पास ले जायें। उद्योग संगठनों ने कहा है कि दरों में कटौती से जो भी लाभ होगा, उसका फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि अगर दर कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं मिलने की वित्त मंत्रियों की भागीदारी बाती जीएसटी परिषद ने बुधवार को शुरू कर दिया है। इसके लिए अनुमति है। विकास और प्रभावित आधार पर 48,000 करोड़ रुपये होंगे। इरिपोर्ट के अनुसार, विकास और प्रभावित मैट्रिक्स को देखते हुए न्यूतम राजस्व हानि 3,700 करोड़ रुपये रखने का अनुमान है। इसका राजस्वपूर्ण परिषद की विकासताती है।

जीएसटी की विवाद की संभावना नहीं: अग्रवाल

जीएसटी कटौती से दोपहिया वाहनों की बिक्री पांच से छह प्रतिशत बढ़ेगी: क्रिसिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वाहनों पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से चालू चित्र वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री पांच से छह प्रतिशत बढ़ जाने की उम्मीद है। जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक बयान में कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की 22 सिंतंबर से प्रभावी होने वाली पांच प्रतिशत और उदारता 18, 22 सिंतंबर से मोटरवाहन क्षेत्र में मांग फिर से बढ़ेगी।

चाहिए। बयान के मुताबिक, चालू चित्र वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में पांच से छह प्रतिशत का वृद्धि होने की वृद्धि होने का अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहन के मुताबिक, चालू चित्र वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि जीएसटी का लोन क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो से तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।



